भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2927

06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार-वर्ष को तय करना

2927. डॉ. सी. एम. रमेशः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार-वर्ष को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू की है, यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई के लिए प्रस्तावित आधार वर्ष क्या है;

(ग) सीपीआई के लिए कौन-कौन सी मदें ली गई हैं और यह मौजूदा बास्केट से किस प्रकार भिन्न है; और

(घ) क्या सरकार आर्थिक जनगणना, सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण और निजी पूंजीगत व्यय सर्वेक्षण कराने जा रही है, यदि हां, तो समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): जी हां, मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार वर्ष को संशोधित करने पर काम कर रहा है। नए डेटा स्रोतों के संकलन और समावेशन की पद्धति को अद्यतन करके अर्थव्यवस्था में हो रहे अवसंरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से कैप्चर करने के लिए आधार वर्ष को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ।

(ख): जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष 2022-23 है, और सीपीआई के लिए प्रस्तावित आधार वर्ष 2024 है।

(ग): संशोधित सूचकांक में, सीपीआई के लिए वर्ष 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से प्राप्त वस्तुओं की सूची और उनके संबंधित अधिमान का उपयोग किया गया है।

(घ): मंत्रालय ने नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश इरादों पर अपना पहला अग्रदर्शी सर्वेक्षण का आयोजन किया है और सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं। मंत्रालय ने निगमित सेवा क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर एक प्रायोगिक अध्ययन भी किया है। अगली आर्थिक गणना अर्थात 8वीं आर्थिक गणना कराने का निर्णय अभी लिया जाना है।